भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

31.08.2024 **1945बजे**

'' मुख्य समाचार''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जताई आवश्यकता।
- प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने दुबई स्थित ई.एफ.एस. ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित।
- प्रदेश में नशे के खिलाफ ज़िला स्तर पर चलाया जाएगा विशेष अभियान– पंचायती राज संस्थानों व पंचायत समिति सदस्यों को किया जाएगा शामिल।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप– कर्ज के लिए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के जी.पी.एफ. को रखा गिरवी।

प्रधानमंत्री–न्यायपालिका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली् के भारत मंडपम में ज़िला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं लेकिन और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च् न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष, भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के अधिक परिपक्व होने की भी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में

न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और यह अपने आप में ही एक बड़ी जिम्मेरदारी है।

समझौता ज्ञापन

प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और दुबई स्थित ई.एफ.एस. फैसिलिटी सर्विसिज़ ग्रुप लिमिटेड के बीच आज शिमला में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को विदेशों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भविष्य में भी युवाओं को इस तरह के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार रोज़गार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले लगभग 20 माह के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31 हज़ार से अधिक पद सृजित किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 उम्मीदवारों को विदेश में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती से उत्पादित 20 क्विंटल अनाज की खरीद प्रति परिवार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत 40 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 30 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मक्का की खरीद की जाएगी। कृषि मंत्री आज कांगड़ा ज़िला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की मैरा बुसकाड़ा पंचायत में 9 ट्यूबवैल का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि भरमाण क्षेत्र में 5 करोड़ 31 लाख

रूपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवैलों से करीब एक सौ 25 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सितम्बर माह से प्रदेश में पशुओं की गणना शुरू की जाएगी और डिजिटल ऐप पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र की धन्यारा पंचायत में एच.पी. शिवा परियोजना के तहत लीची पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इस कलस्टर में 17 हैक्टेयर भूमि पर लीची के 13 हज़ार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे जिससे 65 परिवार लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित शिवा परियोजना पर एक हज़ार 3 सौ 98 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं और ये परियोजना प्रदेश के 7 ज़िलों में चलाई जा रही है। उन्होंने कलस्टर से जुड़ने वाले बागवानों से जागरूक रहने और अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश की आर्थिकी मज़बूत होगी और इसके पूरा होने पर 15 हज़ार से अधिक बागवान परियोजना से जुड़ जाएंगे।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला ज़िले में ठियोग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टियाली के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार प्रयासरत है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले वर्ष में लगभग 5 हज़ार 8 सौ रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी और इसमें से अभी तक 2 हज़ार 8 सौ पदों पर बैचवाईज़ माध्यम से नियुक्ति की जा चुकी है।

राज्यपाल

प्रदेश में नशे के खिलाफ ज़िलास्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसमें पंचायती राज संस्थानों व पंचायत समिति सदस्यों को भी शामिल

किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने राजभवन शिमला में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया। राज्यपाल ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के आदेश दिए ताकि इसके लिए जल्द उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के खिलाफ आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित होना बेहद ज़रूरी है। राज्यपाल ने ग्रामीण स्तर पर जनता को वीडियो संदेश व प्रचार सामग्री के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस दौरान अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल को सभी स्तरों पर हर संभव विभागीय सहयोग का भरोसा भी दिया।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने 18 महीने के कार्यकाल में 24 हज़ार करोड़ से अधिक का कर्ज ले लिया है और इस साल के अंत तक राज्य पर कर्ज एक लाख करोड़ के पास पहुंच जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के जी.पी.एफ. को भी गिरवी रख कर कर्ज लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि डेढ़ साल के कार्यकाल में हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और कांग्रेस सरकार प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की तरफ ले जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार अपने मंत्रियों और सी.पी.एस. का वेतन दो महीने के लिए विलंबित करने की घोषणा करती है, दूसरी तरफ उनकी असंवैधानिक नियुक्ति को बचाने के लिए करोड़ों रूपए दिल्ली के वकीलों पर खर्च करती है। इस बीच, प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते हिमाचल पर कर्ज का बोझ अगले वित्त वर्ष से पहले एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा।

ट्रैकिंग अभियान

खरगा कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने आज खरगा युद्ध स्मारक, विजय स्मारक अंबाला छावनी में 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पिन पार्वती घाटी में शुरू किए गए ट्रैकिंग अभियान **क्षितिज के पार** के सफल समापन पर पाइन डिवीज़न वॉरियर्ज़ के अभियान दल का स्वागत किया। मेजर पुनीत कुमार के नेतृत्व में 15 सदस्यीय इस दल ने मड से अपना अभियान शुरू किया और पिन पास, मतलाई, ओडी थैच, खीर गंगा, मणिकर्ण और पिन पार्वती घाटी से होते हुए ये दल आगे बढ़ा। लैफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने दल के सदस्यों को उनके समर्पण, साहस और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने की शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में साहस व समन्वय को बढ़ावा देना था।

परिचर्चा

आकाशवाणी शिमला के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे **''हृदय रोग, इसके बचाव एवं निदान विषय पर विशेष भेंट वार्ता'' प्रस्तुत की जाएगी**। जिसमें आईजीएमसी शिमला के हृदय रोग विशेषज्ञ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर पी.सी. नेगी श्रोताओं को हृदय रोग से संबंधित विशेष जानकारी देंगे।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आज मशोबरा व सुन्नी की 3 दिवसीय खण्डस्तरीय अंडर–19 छात्राओं की खेल प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पाहल, नीन व घैणी पंचायत के लिए उठाऊ पेयजल योजना के तहत 10 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा रही है जिसका निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि देवीधार से न्योट सड़क निर्माण के लिए 15 करोड़

रूपए का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा जा चुका है जिसकी मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

संजय अवस्थी

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी गांवों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। सोलन ज़िले के अर्की विधानसभा क्षेत्र की कोटली पंचायत में आज कोठी–कोलका–चम्यावल मार्ग के भूमि पूजन के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। संजय अवस्थी ने कहा कि सोलन ज़िले में इस वित्त वर्ष में सड़कों व पुलों के निर्माण पर एक सौ 30 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जताई आवश्यकता।
- प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने दुबई स्थित ई.एफ.एस. ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित।
- प्रदेश में नशे के खिलाफ ज़िला स्तर पर चलाया जाएगा विशेष अभियान– पंचायती राज संस्थानों व पंचायत समिति सदस्यों को किया जाएगा शामिल।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप– कर्ज के लिए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के जी.पी.एफ. को रखा गिरवी।